

Soviet experts are not in a position to undertake or to give any advice or assistance as to what should be done. Whether we should postpone the work for the time being till such time as we get the expertise or we should seek the co-operation of some western countries are matters under careful consideration of the Government, and I would beg of the hon. Members not to reach any conclusions till the Government make up its mind and put their conclusions before Parliament.

#### RETAIL OUTLETS COMMITTEE

+

\*550. SHRI UMANATH :  
SHRI P. P. ESTHOSE :  
SHRI E. K. NAYANAR :  
SHRI P. RAMAMURTHY :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 530 on the 7th December, 1967 and state :

(a) whether Government have considered the report of the Retail Outlets Committee; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have decided to accept and adopt all the recommendations made by the Retail Outlets Committee.

SHRI UMANATH : May I know what are the main recommendations made by the Committee ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : There are a number of recommendations. For the information of the hon. Member, I may state that we have already laid copies of the report in the Parliament Library.

MR. SPEAKER : Very well; it is available.

SHRI UMANATH : One of the allegations against the foreign oil companies is that since they are allowed to make retail sales of part of the oil, they are fixing the prices in such a way as to undercut the prices so as to defeat the public sector undertakings in the industry. So, I would like to know whether the Government have examined this aspect of the question and, if so, what action have they taken.

SHRI RAGHU RAMAIAH : The prices are all determined and there is no question of their having special prices for them.

#### COAL AND NAPHTHA BASED FERTILIZER PLANTS

\*553. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have made any comparative study of the advantages and disadvantages of the Coal-based and naphtha-based fertilizer plants in India; and

(b) if so, the results of that study ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). A preliminary study has shown that the comparative economics of naphtha based and coal-based fertilizer plants depend upon various factors such as process routes, initial investment, size of the plant, its location vis-a-vis market, cost of raw materials and utilities, the product mix and the sale price. Accordingly, a more detailed study with reference to particular locations has been undertaken. It is in progress.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि मिर्जापुर यू०पी० में जो फर्टिलाइजर प्लांट बनने जा रहा है, वह नेफ्था-बेस्ड होगा या कोल-बेस्ड और क्या वह प्राइवेट सेक्टर में होगा या पब्लिक सेक्टर में, यदि वह प्राइवेट सेक्टर में होगा, तो क्यों ।

**पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :** मिर्जापुर में जो प्लांट बनेगा, वह नेफ्था-बेस्ट होगा और प्राइवेट सेक्टर में होगा। वह प्राइवेट सेक्टर में इसलिए होगा कि पब्लिक सेक्टर में अगले दो तीन सालों के लिए हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसलिए हम फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में प्लांट लगाने की इजाजत दे रहे हैं। शायद आनरेबल मेम्बर को पता होगा कि एफ० सी० आई० और एफ० ए० सी० टी० की तरफ से चार नये प्लांट डाले जा रहे हैं। हम मद्रास फर्टिलाइजर्स में एक पांचवां प्लांट डाल रहे हैं। उसके साथ-साथ ट्राम्बे में बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन का फैसला हुआ है। इसके अलावा हम सिन्दरी का रेफ़िनलाइजेशन और माइक्रोलाइजेशन करने जा रहे हैं।

**श्री शिव चन्द्र झा :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के वह कौन हज़रत हैं, जिनकी मार्फ़त यह प्लांट लगाया जायेगा। क्या उनको लाइसेंस दिया जायेगा या परमिशन दी जायेगी और क्या उसकी छान-बीन हो चुकी है?

**श्री अशोक मेहता :** उनको लेटर आफ इंडेंट दिया गया है। कम्पनी का नाम है हिन्दुस्तान एलुमिनियम।

**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोरवा में जो कोल-बेस्ड रासायनिक खाद का कारखाना डालने की बात चल रही है, उसका काम किस स्टेज पर है इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट से क्या-क्या सहूलियतें चाहिए, क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट ने उनको देना मंज़ूर कर लिया और शासन इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लेने जा रहा है?

**श्री अशोक मेहता :** उसका जवाब मेरे साथी ने दिया कि कुछ साइट्स के ऊपर तफ़सील में हम वहां कोल बेस्ड प्लांट करें तो

उसमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा और कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या रहेगी और नाफ्था इसके मुकाबिले में कितनी हद तक फायदेमन्द होगा यह नहीं होगा इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल चल रही है और उसमें कोरवा भी एक जगह है।

**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट से जो पत्र आया है, उन्होंने उसमें केन्द्र द्वारा चाही गई सुविधा दी है।

**श्री अशोक मेहता :** सुविधा जो स्टेट गवर्नमेन्ट ने दी है उसको भी मद्देनजर रख कर ही वहां का जो सर्वे है वह हो रहा है।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या मंत्री महोदय बताएं कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन के द्वारा जो टेक्नोएकॉनामिक स्टडी कमेटी बैठी थी, उसने रिपोर्ट दी है कि कोल बेस्ड फर्टिलाइजर नाफ्था बेस्ड फर्टिलाइजर से सस्ता बनेगा? वह 308 रुपये टन पड़ेगा जबकि नाफ्था बेस्ड फर्टिलाइजर 375 रुपये टन पड़ेगा। यदि ऐसा है तो कोल बेस्ड फर्टिलाइजर के कारखाने क्यों नहीं खोले जाते हैं?

**श्री अशोक मेहता :** ऐसा नहीं है। दुनिया के अन्दर बहुत कम ऐसी जगह है कि जहां कोल-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट बन रहे हैं। आनरेबल मेम्बर साहब जानना चाहेंगे तो मालूमात आसानी से मिल सकती है। लेकिन कुछ जगहें, विशिष्ट जगहें ऐसी हैं जहां या तो आसानी से कोल मिलने से या सस्ते दाम में वहां कोल मिल सकता है या वहां नजदीक पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्ट की कास्ट बच जाती है, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश है कि कहीं ऐसा कोल बेस्ड प्लांट हम चालू करें। लेकिन एकोनामिक स्थिति जैसी है उस में अभी नहीं कर सकते।

**SHRI P. VISWAMBHARAN :** Sir, there are certain proposals to start a naphtha-based petro-chemical complex in Cochin.

MR. SPEAKER : Now we will cover the whole of India ?

SHRI P. VISWAMBHARAN : The Minister has mentioned so many projects.

MR. SPEAKER : This question is not about any particular place. Let us go to the next question.

SHRI K. SURAYANARAYANA—  
rose—

MR. SPEAKER : You want to ask about Kothagudim ? We cannot cover the whole of India in this question. He may also resume his seat.

SHRI P. VISWAMBHARAN : The Minister has mentioned other projects. Why did not he mention this also? What is the position in regard to the proposed naphtha-based petro-chemical complex in Cochin ?

MR. SPEAKER : No, please. We cannot go from State to State.

श्री रवि राय : झा साहब के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कुछ धीमी आवाज में कहा कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम फॅक्ट्री को दिया गया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सज्जन हैं जो इस को चला रहे हैं?

श्री धरमोद मेहता : काफी लोग उसके शेयर होल्डर होंगे लेकिन उसके चलाने वाली बिरला कम्पनी है, वह तो आप जानते हैं।

#### INCOME-TAX CASES

\*554. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pending assessment of Income-tax cases have been progressively rising during the last six years;

(b) if so, what was the number of pending assessment cases in 1961 and what was the number at the end of 1967; and

L13 LSS/68—2

(c) how long it would take to complete the back-log as a result of the steps taken to clear the pending assessment cases and collect the arrears ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of pending assessment cases as on 31st March, 1961 and 31st March, 1967 was 6,19,117 and 23,47,513 respectively.

(c) It is not possible to estimate the exact time it would take to clear the back-log of pending assessments and collect the arrears though all effective steps are being taken to do so as soon as possible.

श्री प्रेम चंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि 1961 के 6 लाख से ज्यादा केसेज बाकी हैं और 1967 से 23 लाख केसेज इनकम टैक्स के बाकी हैं, तो क्या यह दुस्त है कि इनकम टैक्स आफिसर्स मार्च महीने में जितने केसेज की असेसमेंट करते हैं वह सारे साल की असेसमेंट से एक-चौथाई हिस्सा होता है और यह एक-चौथाई हिस्सा वह इतनी हरी में करते हैं, इतनी जल्दी में केसेज करते हैं कि 50 प्रतिशत केसेज की अपीलें होती जिसकी वजह से यह सरकार का सारे का सारा रुपया, करोड़ों रुपया, उनसे मिल कर वसूल नहीं होने देते, वह वसूल नहीं होने देना चाहते न उस के लिए कुछ करते हैं, तो क्या सरकार को मालूम है कि यह सारी कार्यवाही पूंजीपति लोग उनसे मिल कर करते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान् जल्दबाजी तो तभी होती है जबकि उस समय की सीमा तक हम पहुंच जाते हैं जब तक कि असेसमेंट कर सकते हैं। इसलिए कि कोई असेसमेंट से छूट न जाय, इसलिए जल्दी की जाती है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ इसी सिलसिले में कि जितना रुपया बाकी है इस